सदस्य बनें

सच और सरोकार की पत्रकारिता से जुड़ें
वार्षिक सदस्यता : ₹ 500 मात्र

पूरा वर्ष अखबार नि:शुल्क
पैनल विज्ञापन दें
अपने व्यवसाय/संस्था का प्रचार करें 'जन जन विचार' में।
किफायती ● प्रभावी ● विश्वसनीय
संपर्क : 69001 26012

जन जन की बात जन जन तक

जन जन विचार

साप्ताहिक

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367 ::Guwahati, Friday, 3 April, 2026 :: Vol-12 Year-1 :: शुक्रवार ।3 अप्रैल 2026 । शक संवत 1948 ।चैत्र । कृष्ण । द्वितीया ।:: पृष्ठ-12 । मूल्य – 5 रुपए।

जन चिंतन

नागरिक जिम्मेदारी

भारत एक जीवंत लोकतंत्र है—यह केवल चुनावों का देश नहीं, बल्कि विचारों, संवाद और सहभागिता की निरंतर प्रक्रिया है। आज जब हम तेजी से बदलते सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी दौर से गुजर रहे हैं, तब 'जन चिंतन' की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

लोकतंत्र की असली ताकत जनता की जागरूकता में निहित होती है। यदि नागरिक केवल मतदान तक ही अपनी भूमिका सीमित कर लें, तो लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। जरूरी है कि हम अपने आसपास की समस्याओं—चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो या स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही—पर निरंतर विचार करें और समाधान की दिशा में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

आज का भारत अवसरों का भारत है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। डिजिटल क्रांति ने जहां सूचनाओं को सुलभ बनाया है, **शेष पृष्ठ 2 पर**

डिब्रूगढ़ के एक चाय बागान में महिला श्रमिकों के साथ पत्तियां तोड़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

भाजपा की हैट्रिक मोदी का दावा

डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में जोरदार चुनावी अभियान की शुरुआत की और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए राज्य में लगातार तीसरी भाजपा-एनडीए जीत की भविष्यवाणी की। गोगामुख और डिब्रूगढ़ में आयोजित रैलियों में मोदी ने 5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश योजना की घोषणा की, समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया और भाजपा शासन में हुए विकास और सुधारों को उजागर किया।

असम में भाजपा लाएगी यूसीसी

◆ चुनाव घोषणापत्र जारी ◆अरुणोदय की राशि होगी 3000 ◆लैंड जिहाद पर कड़ा प्रहार ◆नौकरियों व रोजगार का वादा

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

गुवाहाटी में 31 मार्च को भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने महिलाओं के सशक्तिकरण और कानूनी समानता पर जोर देते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और 'अरुणोदय' योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।

घोषणापत्र में कुल 31 प्रमुख वादे शामिल हैं। शर्मा ने स्पष्ट किया कि संविधान की छठी अनुसूची और आदिवासी क्षेत्रों को यूसीसी से छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा, 'हम निर्भर राज्य नहीं बनना चाहते; हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय विकास में योगदान देना है।' इसके अलावा, आगामी दो सालों में बाढ़ नियंत्रण के लिए 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का आश्वासन दिया गया।

महिलाओं के लिए सशक्तिकरण पहल

मुख्यमंत्री ने 'लखपति दीदी' योजना की घोषणा की, जिसके तहत पूरे राज्य की 40 लाख महिलाओं को 25,000 रुपए तक सहायता दी जाएगी। रोजगार सृजन के लिए अगले पांच वर्षों में 2 लाख नई नौकरियों का वादा किया गया। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय

और एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की योजना भी शामिल है।

घोषणा पत्र लांच में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, सर्वानंद सोनोवाल और असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप **शेष पृष्ठ 2 पर**

यूपीपीएल ने जारी किया 'जन घोषणा पत्र'

कोकराझार। असम विधानसभा चुनाव 2026 के पहले, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) ने बीटीआर में समावेशी विकास, शांति और सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर केंद्रित अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया।

मुख्य बिंदु और वादे :

शांति और सामुदायिक सौहार्द

पार्टी ने संवाद, समावेशी शासन और उप-प्रभाग स्तर पर शांति समितियों के गठन के जरिए समुदायों में सामंजस्य बनाए रखने का वादा किया।

बीटीआर शांति समझौते की पूर्ण लागू:

2020 के बीटीआर शांति समझौते को तेजी से लागू करना और संवैधानिक व संस्थागत सुदृढ़ता लाने के प्रयास। 60 एमसीएलए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण और बीटीआर सरकार के लिए सीधे केंद्रीय वित्त पोषण की योजना। **शेष पृष्ठ 3 पर**

कांग्रेस की पांच गारंटियां, धार्मिक भेदभाव पर जेल

गुवाहाटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मार्च 2026 में घोषणापत्र जारी किया, जिसमें मुख्य रूप से वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य और भूमि अधिकार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुख्य 5 वादे: महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता – हर महिला के बैंक खाते में मासिक अनिवार्य नकद राशि। साथ ही व्यवसाय शुरू या बढ़ाने के लिए एकमुश्त 50,000 रुपए का ग्रांट। **शेष पृष्ठ 3 पर**

जुबिन की मौत दुर्घटना बोली सिंगापुर पुलिस

गुवाहाटी। असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच अब आधिकारिक रूप से सिंगापुर पुलिस द्वारा पूरी कर ली गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि हत्या या किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि के कोई सबूत नहीं मिले और यह घटना दुर्घटनावश डूबने का मामला थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा 19 **शेष पृष्ठ 3 पर**

अंदर पढ़ें

2. एनडीए और असोम की बीच कड़ी टक्कर
3. राहुल का वादा, लागू करेंगे 244 (ए)
5. नीतीश छोड़ेंगे सीएम पद...
7. 'बाहरी वोटरों' की बंगाल में एंट्री की कोशिश
8. नक्सल डेडलाइन खत्म, 'नई रणनीति' पर फोकस
9. थमेगा मध्य पूर्व का संकट!
10. एफएलएन : शिक्षा की पहली मजबूत नींव
11. जुलाई में जिम्बाब्वे का दौरा करेगी टीम इंडिया

एनडीए और असोम की बीच कड़ी टक्कर

विधानसभा चुनाव : कामरूप मेट्रो जिला

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

कामरूप मेट्रो जिले की पांच प्रमुख विधानसभा सीटों में 2026 के असम विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाली असम सम्मिलित मोर्चा (असोम) के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा जैसे बड़े नाम और रणनीतिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की भाजपा की रणनीति कारगर साबित हो सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस और सहयोगी दलों ने असोम का नेतृत्व करते हुए कुछ शहरी सीटें जैसे मध्य गुवाहाटी को अपने सहयोगी असम जातीय परिषद को सौंप दी हैं ताकि विरोधी वोटों का समेकन किया जा सके।

गुवाहाटी की ये पांच सीटें शहरी मतदाता और अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्र होने के कारण चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

विधानसभा क्षेत्र	एनडीए उम्मीदवार	असोम उम्मीदवार	मुख्य हाइलाइट
जालुकबाड़ी	डॉ. हिमंत विश्व शर्मा	बिदिशा नियोग (कांग्रेस)	मुख्यमंत्री का हाई-प्रोफाइल क्षेत्र
दिसपुर	प्रद्युत बरदलै	मीरा बरठाकुर गोस्वामी (कांग्रेस)	बरदलै हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए
मध्य गुवाहाटी	विजय कुमार गुप्ता	कुंकी चौधरी (एजेपी)	हालिया डेलिमिटेशन के बाद बनी बहु-पक्षीय टक्कर
न्यू गुवाहाटी	दिप्लु रंजन शर्मा	शांतनु बोरा (कांग्रेस)	शहरी क्षेत्र, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए निर्णायक
डिमोरिया (एससी)	डॉ. तपन दास (अगप)	किशोर कुमार बरुवा (कांग्रेस)	भाजपा के सहयोगी, अगप द्वारा प्रतिनिधित्व

असम में मुसलमानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस जिम्मेवार : ओवैसी

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

'असदुद्दीन ओवैसी का असम दौरा चुनावी तापमान को और तेज कर गया है। गुवाहाटी में दिए गए उनके बयान—जहां उन्होंने कांग्रेस को भाजपा के उभार के लिए जिम्मेदार ठहराया और 50,000 मुस्लिम घरों के ध्वस्तीकरण का आरोप लगाया—ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। ओवैसी का यह हमला केवल भाजपा पर नहीं, बल्कि कांग्रेस की भूमिका पर भी सीधा सवाल है। उनका संदेश साफ है—विपक्ष की कमजोरी ने सत्तारूढ़ ताकतों को मजबूत किया। वहीं हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार पर 'नफरत की राजनीति' का आरोप लगाकर उन्होंने अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश की है।

साप्ताहिक राशिफल

3 से 9 अप्रैल 2026 ।। विक्रम संवत 2083–**मास** : चैत्र, **पक्ष** : कृष्ण, **तिथि** : द्वितीया

मेष
इस सप्ताह नए काम की शुरुआत के योग हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें। धन लाभ संभव है।

वृषभ
खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी में स्थिरता रहेगी।

मिथुन
करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे। नए संपर्क फायदेमंद रहेंगे। यात्रा का योग बन सकता है।

कर्क
भावनात्मक तनाव रह सकता है, लेकिन परिवार साथ देगा। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सुधार होगा।

सिंह
सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कन्या
काम का दबाव ज्यादा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी।

तुला
प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। साझेदारी के काम में लाभ होगा। नए अवसर मिलेंगे।

वृश्चिक
पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय में बदलाव के संकेत हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

धनु
भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी। यात्रा लाभदायक होगी।

मकर
मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग रहेगा।

कुंभ
नई योजनाएं सफल होंगी। दोस्तों से मदद मिलेगी। निवेश के लिए अच्छा समय है।

कुंभ
मन थोड़ा परेशान रह सकता है। ध्यान और योग से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

5 रविवार :संकष्टी चतुर्थी

●ज्योतिर्विद् आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

पृष्ठ 1 का शेषांश...

नागरिक जिम्मेदारी

वहीं फर्जी खबरों और भ्रामक प्रचार का खतरा भी बढ़ा है। ऐसे में नागरिकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे सूचनाओं को परखें, सत्य और असत्य में अंतर समझें और जिम्मेदारी के साथ अपनी राय बनाएं। युवा पीढ़ी इस परिवर्तन का केंद्र है। उनके पास ऊर्जा है, नई सोच है और बदलाव की क्षमता है। यदि यह ऊर्जा सही दिशा में लगाई जाए, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली को भी केवल रोजगार तक सीमित न रहकर नागरिक मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देना होगा।

हमारे समाज में संवाद की संस्कृति को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। असहमति लोकतंत्र का आधार है, लेकिन असहमति को वैमनस्य में बदलना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है। हमें यह समझना होगा कि विचारों की विविधता ही भारत की असली ताकत है।

असम में भाजपा...

सैकिया भी मौजूद थे। साइकिया ने चुनाव की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि 2,45,000 सुझावों के आधार पर घोषणापत्र तैयार किया गया, जो जनता की भागीदारी को दर्शाता है। भाजपा असम गण परिषद (अगप) और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) के साथ गठबंधन कर तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य रख रही है। **विपक्ष का रुख :** कांग्रेस ने भी पांच मुख्य वादों के साथ प्रतिस्पर्धी घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं के लिए मासिक नकद हस्तांतरण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,250 रुपये पेंशन, परिवारों के लिए 25 लाख रुपये तक स्वास्थ्य कवरेज और 10 लाख स्वदेशी लोगों के लिए भूमि अधिकार शामिल हैं। **चुनाव तिथियां :** असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को घोषित की जाएगी।

जुबिन की मौत...

सितंबर 2025 को एक निजी यॉट पर हुआ। शुरुआत में जुबिन लाइफ जैकेट पहनकर तैर रहे थे, लेकिन बाद में यॉट लौटने के बाद इसे उतार दिया। फिर अकेले और बिना जीवनरक्षा जैकेट के पानी में लौटे, और तैरने का प्रयास करते समय बेहोश हो गए। यॉट पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें बचाया और सीपीआर दी, लेकिन उन्हें सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में डूबने को मौत का कारण बताया गया। उनके रक्त में उच्च स्तर की शराब (एथेनॉल) पाई गई, जिससे समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता प्रभावित हुई थी। अन्य दवाओं का स्तर सामान्य था और उनके ज्ञात स्वास्थ्य हालात (मिर्गी और उच्च रक्तचाप) के अनुरूप था।

सिंगापुर के कोरोनर की जांच प्रक्रिया में भी यही निष्कर्ष आया और 25 मार्च 2026 को मृत्युदर दुर्घटना घोषित की गई। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि अफवाहों और अटकलों से बचें और परिवार व प्रशंसकों के प्रति संवेदना जताई। जुबिन गर्ग की याद उनके संगीत में हमेशा जीवित रहेगी, और यह घटना एक दुखद लेकिन स्पष्ट दुर्घटना के रूप में दर्ज हुई।

राहुल का वादा, लागू करेंगे 244 (ए)

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी/बोकाजान

असम विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार जोरों पर है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कार्बी आंग्लांग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर अनुच्छेद 244(ए) का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी, जिससे आदिवासी समुदायों को स्वशासन और स्थानीय निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा।

गांधी ने कहा, 'एक बार अनुच्छेद 244(ए) लागू होने के बाद, गुवाहाटी से कोई कार्बी आंग्लांग के लोगों पर शासन नहीं करेगा। निर्णय लेने का अधिकार आप लोगों के हाथ में होगा।' उन्होंने इसे आदिवासी अधिकारों की रक्षा और विकेंद्रीकृत शासन सुनिश्चित करने का माध्यम बताया।

भाजपा पर तंज और भ्रष्टाचार का आरोप

राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि असम में शासन केंद्र के नियंत्रण में है। उन्होंने राज्य की भूमि भाजपा सरकार द्वारा लोगों से छीनी गई और बड़े कॉरपोरेट समूहों को सौंप दी गई होने का आरोप लगाया।

उन्होंने नाम लिए गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और बाबा रामदेव के कारोबारों का, और कहा कि तीन बड़े कॉरपोरेट समूहों को लगभग 98,400 बीघा भूमि दी गई है। गांधी ने कहा, 'असम अब जमीन एटीएम बन गया है।'

कांग्रेस की कल्याण योजनाएँ

राहुल गांधी ने अपने भाषण में कांग्रेस के वादों का विवरण भी दिया:

◆महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता।

◆वरिष्ठ नागरिकों को ?1,250 मासिक पेंशन।

◆10 लाख आदिवासी लोगों को स्थायी भूमि पट्टा।

◆प्रत्येक परिवार को ?25 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा।

◆सिंगापुर में मृतक गायक जुबिन गर्ग के मामले में सत्ता में आने पर

◆100 दिन में न्याय सुनिश्चित करने का वादा।

उन्होंने भाजपा के शासन मॉडल पर अत्यधिक केंद्रीकरण और असम के विकास में विदेशी नीति के नकारात्मक प्रभाव का भी आरोप लगाया।

सच और दिखावा में अंतर समझती है जनता : उरांग

जन जन विचार
...✍ आनंद शर्मा
ढेकियाजुली

असम के ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प और बहुआयामी हो गया है। गांव-देहात की चौपालों से लेकर कस्बों के बाजार तक, हर जगह एक ही चर्चा है—क्या इस बार सत्ता में बदलाव होगा या फिर विकास के दावों पर जनता मुहर लगाएगी। इसी बीच कांग्रेस उम्मीदवार बतास उरांग ने अपने चुनावी अभियान को तेज करते हुए खुद को जनता की आवाज के रूप में प्रस्तुत किया है। वे न केवल अपने राजनीतिक अनुभव, बल्कि जमीनी जुड़ाव और सामाजिक समीकरणों के आधार पर इस चुनाव को एक नए मोड़ पर ले जाने का दावा कर रहे हैं।

बातचीत के दौरान बतास उरांग ने खुलकर अपनी राजनीतिक यात्रा और मौजूदा हालात पर बात की। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहे और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहे। उनके अनुसार, पिछले दोनों विधानसभा चुनावों में उन्होंने वर्तमान विधायक और मंत्री अशोक सिंघल के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम किया, जिसका सीधा लाभ उन्हें चुनावी जीत के रूप में मिला। उरांग का मानना है कि उस समय कार्यकर्ताओं और विशेष रूप से आदिवासी समाज का समर्थन जुटाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और जनता वास्तविकता को समझने लगी है।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज की स्थिति में मंत्री के पास जमीनी समर्थन बेहद सीमित रह गया है, जबकि उनका खुद का आधार लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आदिवासी समाज के 30 हजार से अधिक मतदाता उनके साथ खड़े हैं और यह समर्थन सिर्फ जातीय पहचान पर आधारित नहीं, बल्कि वर्षों के विश्वास और संपर्क का परिणाम है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बोड़ो, नेपाली, बंगाली, असमीया और हिंदी भाषी आदि समुदायों के लोगों से उनके मधुर संबंध हैं, जो चुनाव में उनके पक्ष में एक बड़ा कारक साबित होंगे।

नाजिरा में 8.55 लाख रुपए जब्त

जन जन विचार
...✍ नाजिरा

असम विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ लागू आचार संहिता के बीच राज्यभर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं। इसी क्रम में नाजिरा के बरटल क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त तलाशी अभियान में 8 लाख 55 हजार रुपये नकद बरामद किए गए।

यह रकम एक स्कॉर्पियो वाहन से कार्टून में छिपाकर ले जाई जा रही थी। वाहन की जांच के दौरान पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद तलाशी में यह बड़ी राशि सामने आई।

तलाशी के दौरान वाहन से जय भारत पार्टी (जजपा) का झंडा भी बरामद हुआ है। इससे पुलिस को संदेह है कि यह राशि किसी चुनावी उम्मीदवार तक पहुंचाने के उद्देश्य से ले जाई जा रही थी।

हालांकि, इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और जांच जारी है।

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद राज्यभर में लगातार चेकिंग और छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। नियमों के अनुसार, तय सीमा से अधिक नकदी ले जाने पर वैध स्रोत का प्रमाण देना अनिवार्य होता है।

नाजिरा की इस कार्रवाई को चुनाव से पहले सतर्क प्रशासन और सक्रिय निगरानी का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

कांग्रेस की पांच ....

कैशलेस स्वास्थ्य बीमा - प्रत्येक परिवार के लिए 25 लाख रुपए का कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस।

आदिवासी लोगों के लिए भूमि अधिकार - लगभग 10 लाख खिलंजिया निवासियों को स्थायी भूमि पट्टा।

वरिष्ठ नागरिक पेंशन - हर वरिष्ठ नागरिक को मासिक 1,250 रुपए की पेंशन और बुजुर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन।

जुबिन गर्ग के लिए न्याय - सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर न्याय सुनिश्चित करने का वादा।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:

सांप्रदायिक सौहार्द कानून - किसी भी व्यक्ति द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव या सांप्रदायिक दंगा करने पर 5 वर्ष तक की जेल।

भूमि पुनर्वितरण - यदि सत्ता में आती है, तो वर्तमान प्रशासन द्वारा कथित रूप से अधिग्रहित भूमि का पुनर्वितरण।

चाय बागान मजदूरों के लिए समर्थन - भूमि अधिकार और कल्याणकारी उपाय।

कांग्रेस इस चुनाव में स्वतंत्र रूप से मुकाबला कर रही है और सीधे लाभ और जमीनी कनेक्शन के आधार पर भाजपा को चुनौती दे रही है।

यूपीपीएल ने जारी किया

भूमि और समुदाय अधिकार: पात्र भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा वितरण और लंबित भूमि विवादों का समाधान।

भाषा और संस्कृति का संवर्धन: स्कूलों में राभा, कोच-राजबोंगशी और संथाली भाषाओं को शिक्षा माध्यम के रूप में बढ़ावा। सभी धार्मिक संस्थानों और नेताओं का समर्थन।

शिक्षा और स्वास्थ्य: छात्रवृत्तियों का विस्तार, बकसा में केंद्रीय विश्वविद्यालय और उदालगुरी में NIT की स्थापना। अस्पतालों में एंबुलेंस सेवा, कैंसर देखभाल और पर्याप्त स्टाफिंग सुनिश्चित करना।

सामाजिक कल्याण: वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांगों का समर्थन और विभिन्न धर्मों के तीर्थयात्रियों के लिए योजनाएँ।

युवा सशक्तिकरण: कौशल प्रशिक्षण केंद्र, फेलोशिप कार्यक्रम और रोजगार-आधारित प्रशिक्षण योजनाएँ।

आर्थिक विकास: सड़कों, पुलों, सिंचाई प्रणालियों और औद्योगिक पार्कों का विकास। किसानों की आय दोगुनी करने, आधुनिक कृषि तकनीक और बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता।

पर्यावरण संरक्षण: राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों की सुरक्षा, मानव-हाथी संघर्ष को कम करना और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा।

पार्टी अध्यक्ष प्रमोद बोरो ने कहा, 'हम BTR में सभी समुदायों के लिए समावेशी, शांतिपूर्ण और विकासोन्मुख शासन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमें विश्वास है कि जनता का समर्थन हमें विजयी बनाएगा।'

चुनाव 9 अप्रैल को होने वाले हैं और यूपीपीएल ने अपने क्षेत्रीय मतदाताओं से शांतिपूर्ण और समृद्ध बीटीआर के लिए समर्थन का आग्रह किया है।

संपादकीय

अमेरिकी हठ

अमेरिका की मौजूदा ईरान नीति अब रणनीति कम और जिद ज्यादा लगने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में शुरू हुआ यह युद्ध जिस स्पष्ट लक्ष्य और ठोस योजना की मांग करता था, वह अब तक नदारद दिखती है। एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी न तो निर्णायक सैन्य सफलता मिली है और न ही ईरान की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव दिखाई देता है। इसके उलट, अमेरिकी सैनिकों की मौत, अरबों डॉलर का नुकसान और वैश्विक अस्थिरता—ये सब इस नीति की विफलता की कहानी कह रहे हैं।

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का विरोध केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि यथार्थ पर आधारित प्रतीत होता है। जब सहयोगी देश दूरी बनाने लगें और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हों, तो यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संकट बन जाता है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस युद्ध का मानवीय मूल्य लगातार बढ़ रहा है—चाहे वह अमेरिकी सैनिक हों या ईरानी नागरिक। ऐसे में जिद छोड़कर कूटनीति की राह अपनाना ही समझदारी है। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, उतना ही अमेरिका की साख और स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगा। अब वक्त है कि हथियार नहीं, संवाद बोले।

सुलगता सवाल ? आपके विचार

अंधविश्वास : कब होगा दूर

झारखंड के हजारीबाग से आई यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज में जड़ें जमा चुके अंधविश्वास का भयावह चेहरा है। एक मां द्वारा अपने ही बच्चे की बलि देना मानवता को झकझोर देने वाला कृत्य है, जो बताता है कि शिक्षा और जागरूकता के दावों के बावजूद हम अब भी अंधे विश्वासों की गिरफ्त में हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 21वीं सदी में भी लोग तथाकथित तांत्रिकों के झांसे में क्यों आ जाते हैं? बीमारी का इलाज विज्ञान और चिकित्सा से होना चाहिए, न कि कुप्रथाओं और हिंसक अनुष्ठानों से। जब एक मां ही अपने बच्चे की सुरक्षा की जगह अंधविश्वास को चुन ले, तो यह केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक तंत्र की भी नाकामी है।

ऐसे मामलों में केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। जरूरत है सख्त कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, गांव-गांव तक वैज्ञानिक सोच पहुंचाने और ढोंगी तांत्रिकों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की। साथ ही, शिक्षा प्रणाली को भी इस दिशा में मजबूत बनाना होगा ताकि बच्चे और अभिभावक दोनों तर्क और विज्ञान पर भरोसा करना सीखें।

यह घटना एक चेतावनी है—अगर अब भी नहीं जागे, तो अंधविश्वास की यह आग और निर्दोष जिंदगियां निगलती रहेगी।

न उठाएं थोथे सवाल

जन जन विचार
...✍ नीरज कुमार दुबे

देखा जाये तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को झकझोर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से भारत पहले अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग चालीस से पैंतालीस प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है उस पर दबाव बढ़ने से कई तरह की अटकलें लगाई गईं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने वाले और मोदी की विदेश नीति को विफल बताने वाले विपक्षी नेताओं को यह देखना चाहिए कि जब भारत के सामने ऊर्जा संकट मंडराया तो दुनिया के वही देश मदद के लिए खड़े हो गए जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों तक भरोसे का रिश्ता बनाया था। खासकर अफ्रीकी देशों से बढ़ते आयात ने यह साबित कर दिया है कि भारत ने समय रहते अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाया था। आज वही रिश्ते और रणनीतिक फैसले भारत की ढाल बनकर खड़े हैं और यही असली कूटनीति की ताकत है।

देखा जाये तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को झकझोर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से भारत पहले अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग चालीस से पैंतालीस प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है उस पर दबाव बढ़ने से कई तरह की अटकलें लगाई गईं। लेकिन भारत न तो घबराया और न ही संकट में फंसा। इसका कारण है मोदी सरकार की दूरदर्शी ऊर्जा नीति और समय रहते उठाए गए रणनीतिक कदम।

आज स्थिति यह है कि भारत में कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी की उपलब्धता एक महीने पहले की तुलना में काफी बेहतर हो चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी प्रकार की ऊर्जा की कमी नहीं है और पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारु बनी हुई है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित रणनीति का परिणाम है।

देखा जाये तो सबसे बड़ा बदलाव आया है ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण में। एक दशक पहले तक भारत केवल 27 देशों से कच्चा तेल लेता था, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 41 हो चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। अमेरिका, रूस, कनाडा, नार्वे से लेकर अफ्रीकी देशों जैसे नाइजीरिया, अल्जीरिया और अंगोला तक भारत ने अपने ऊर्जा संबंधों का विस्तार किया है। एलएनजी के लिए कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और मोजाम्बिक जैसे नए साझेदार जुड़े हैं।

यही नहीं, रणनीतिक भंडारण की दिशा में भी भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पिछले 11 वर्षों में 5.3 मिलियन टन का रणनीतिक तेल भंडार तैयार किया गया है और अतिरिक्त क्षमता पर तेजी से काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत के पास आपूर्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है।

मोदी सरकार ने केवल आपूर्ति बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि प्रबंधन को भी मजबूत किया। चौबीसों घंटे निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया और एक अंतर मंत्रालयी समूह रोज बैठक कर हालात का आकलन कर रहा है। जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए और राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।

यहां सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कूटनीतिक सक्रियता। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान और अमेरिका जैसे देशों के नेताओं से लगातार संपर्क बनाए रखा। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हुई और आपूर्ति बाधित नहीं हुई। यह वही देश हैं जिनसे भारत ने संकट के समय पहले भी सहयोग किया था और आज वही रिश्ते काम आए।

सामरिक दृष्टि से देखें तो यह पूरी स्थिति भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति की बड़ी परीक्षा थी। पश्चिम एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्र में तनाव का सीधा असर भारत पर पड़ सकता था, लेकिन भारत ने अपनी निर्भरता घटाकर इस खतरे को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया। अब होर्मुज मार्ग पर निर्भरता घटकर लगभग तीस प्रतिशत रह गई है।

इसके रणनीतिक निहितार्थ और भी गहरे हैं। भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा कूटनीति का सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है। अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में बढ़ती मौजूदगी भारत को दीर्घकालिक सुरक्षा देती है। साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस जैसे विकल्पों को बढ़ावा देकर एलपीजी पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी काम हो रहा है।

आम जनता पर इसका सकारात्मक असर साफ दिख रहा है। रसोई गैस की आपूर्ति जारी है, भले ही घबराहट में बुकिंग बढ़ने से डिलीवरी में चार से पांच दिन का समय लग रहा हो, लेकिन कहीं भी गैस खत्म होने की खबर नहीं है। किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और पेट्रोल, डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है। यह पूरा घटनाक्रम एक बात साफ करता है कि मोदी सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को केवल नीतिगत मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा माना है। आज जब दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं तब भारत मजबूती से खड़ा है।

बहरहाल, विपक्ष को यह समझना होगा कि विदेश यात्राएं केवल फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होतीं, बल्कि संकट के समय काम आने वाले रिश्ते बनाने के लिए होती हैं। और जब संकट आया, तो वही रिश्ते भारत के लिए कवच बन गए। यही है नई भारत की आक्रामक, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी कूटनीति।

नीतीश छोड़ेंगे सीएम पद, मिलेगी Z+ सिक्योरिटी

10 को रास शपथ, 13 को इस्तीफा

जन जन विचार
...✍ पटना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला सामने आया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इस फैसले ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, नीतीश कुमार 10 अप्रैल को दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं।

इसके बाद 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर तारीखों की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

नीतीश कुमार 30 मार्च को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। करीब 20 वर्षों तक परिषद के सदस्य रहने के बाद उन्होंने संक्षिप्त पत्र के जरिए पद छोड़ा।

जेड+ सिक्योरिटी देने का निर्णय

गृह विभाग ने नीतीश कुमार को जेड+ श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। यह सुरक्षा उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी मिलेगी।

निर्णय उनकी संवेदनशीलता और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए लिया गया है।

बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत फैसला

सरकार ने यह निर्णय बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट-2000 के तहत लिया है। इस कानून के तहत विशिष्ट व्यक्तियों को खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। गृह विभाग ने समीक्षा के बाद उन्हें इस श्रेणी के योग्य माना है।

गृह विभाग द्वारा जारी पत्र में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया गया है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे।

इसके अनुसार उन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

क्या होती है जेड+ सिक्योरिटी

जेड+सिक्योरिटी देश की सबसे उच्च श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। यह उन नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाती है, जिनकी जान को खतरा होता है।

जदयू विधायक के करीबी दोस्त को गोली मारी

पटना। शहर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद दिखे, जब बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मार दी। घटना बोरिंग रोड इलाके की है, जहां जीएस इंक्लेव अपार्टमेंट के पास कारोबारी दिलीप कुमार सिंह पर हमला किया गया और वो सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के फुलवारी विधायक श्याम रजक के बेहद ही करीबी मित्र हैं। मंगलवार रात करीब नौ बजे दिलीप कुमार सिंह ऑफिस से लौटकर अपार्टमेंट पहुंचे थे। कार पार्क करने के बाद जैसे ही वह ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट की ओर बढ़ रहे थे, तभी पीछे से आए दो अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। अपराधियों ने ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग की। इसमें एक गोली उनके पेट के पास लगी, जो आरपार हो गई। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

पूरी घटना अपार्टमेंट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में दिखा कि एक आरोपी हेलमेट पहने हुए था, जिससे उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है।

पटना में छात्रा मौत मामला : अब दिल्ली से होगी जांच की मॉनिटरिंग

पटना: पटना के एक हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच ने नया मोड़ ले लिया है। अब इस संवेदनशील केस की निगरानी सीधे सीबीआई की दिल्ली टीम द्वारा की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद जांच प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली स्तर से मॉनिटरिंग शुरू की गई है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली के एसपी फिलहाल पटना में कैंप कर रहे हैं
वे पूरे केस की जांच की निगरानी कर रहे हैं हालांकि, जांच टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विचार

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है।

कविता

मंगल पांडेय वीर महान,
भारत माँ की थे शान।
अन्याय से जो डरे नहीं,
सच के लिए झुके नहीं।

सिपाही थे बहादुर वो,
दिल में जलता था जोश।
अंग्रेजों से लड़े डटकर,
किया न कभी भी होश खो।

1857 की जंग छेड़ी,
आजादी की राह थी जोड़ी।
पहली चिंगारी बनकर आए,
सबके दिल में आग जगाए।

फांसी से भी डरे नहीं,
देश प्रेम से हटे नहीं।
ऐसे वीर को नमन हमारा,
मंगल पांडेय नाम है प्यारा।

पहेलियां

1. **ऐसी कौन सी चीज है,**
   जो पानी में गिरते ही गीली नहीं होती?
2. **न खाने की चीज, न पीने की।**
   फिर भी रोज़ काम आती है जी।
3. **सिर है, पूंछ है, पर शरीर नहीं, जेब में रहती, मगर जिंदा नहीं।**
4. **ऐसा कौन सा फल है,**
   जिसमें ताला और चाबी दोनों होते हैं?
5. **दिन में सोता, रात में जागता,**
   बिना पंख के उड़ता जाता।
6. **एक ऐसी चीज़ बताओ,**
   जो खुद जलती है और दूसरों को रोशनी देती है।
7. **ऐसा कौन सा जानवर है,**
   जो कभी पानी नहीं पीता?
8. **कान हैं पर सुनती नहीं,**
   पैर हैं पर चलती नहीं।

उत्तर:
परछाई
हवा
सिक्का
केला
चाँद
मोमबत्ती
कंगारू चूहा
कुर्सी

मंगल पांडे : आजादी की पहली चिंगारी

8 अप्रैल को जिनकी पुण्यतिथि है

मंगल पांडे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें 1857 की क्रांति का पहला वीर सिपाही माना जाता है। उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था।

मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में सिपाही थे, लेकिन वे अंग्रेजों के अन्याय से बहुत दुखी थे। उस समय भारतीय सैनिकों को ऐसी कारतूस दी जा रही थीं, जिन पर गाय और सूअर की चर्बी होने की बात कही जाती थी। यह भारतीयों की धार्मिक भावनाओं का अपमान था।

29 मार्च 1857 को बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और संघर्ष का बिगुल बजाया। उनकी इस बहादुरी ने पूरे देश में आजादी की पहली चिंगारी जलाई, जो बाद में बड़े आंदोलन में बदल गई।

अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी, लेकिन उनका साहस और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा।

मंगल पांडे हमें सिखाते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची बहादुरी है। उनके जैसे वीरों की वजह से ही आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं।

उल्लू और कौवों में बैर

एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, मुर्गा, उल्लू आदि प्रमुख पक्षियों ने एक सभा करके यह निश्चय किया कि पक्षियों को अपने नए राजा का चुनाव कर लेना चाहिए। हमारा वर्तमान राजा गरुड़ है, किंतु वह भगवान विष्णु की सेवा-कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि पक्षियों के हित-साधन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता। हमें ऐसा राजा चाहिए जो हमारे बीच रहकर हमारी समस्याओं पर विचार करे और उनका समाधान करे।

यह सभा कई दिन तक चली और अंतत: निर्णय हुआ कि उल्लू को नया राजा बनाया जाए। अभिषेक की तैयारियां होने लगीं। विभिन्न तीर्थों से पवित्र जल मंगवाया गया। सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण-घट भरे गए। वेद-पाठी ब्राह्मणों ने वेद-मंत्रों का गान आरंभ कर दिया। उल्लू राज-सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ पहुंचा।

कौवे को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन-ही-मन सोचने लगा कि यह कैसा समारोह है? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। कौवे को तो किसी ने आमंत्रित भी नहीं किया था, फिर यह यहां क्यों आया? लेकिन सभी ने यह सुना हुआ था कि मनुष्यों में नाई, हिंस्र पशुओं में गीदड़ और पक्षियों में कौवा सबसे चतुर होता है। इसलिए कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले नहीं करना चाहिए, जैसे-

जटिल विषयों पर अकेले विचार नहीं करना चाहिए

स्वादिष्ट भोजन अकेले नहीं खाना चाहिए

सोते हुए लोगों के बीच अकेले जागना उचित नहीं

यात्रा पर अकेले जाना भी संकटपूर्ण होता है—रास्ते में यदि कोई डरपोक व्यक्ति भी मिल जाए तो उसे साथ ले लेना चाहिए।

कौवा बोला, 'मित्रो! यह क्या कर रहे हो? उल्लू को राजा बनाना चाहते हो? अरे, यह तो रात में ही देखता है, दिन में अंधा हो जाता है। ऐसे राजा से हमारी प्रजा का क्या भला होगा? दिन के समय शत्रु आक्रमण करेंगे तो यह क्या करेगा? सोएगा?'

यह सुनकर सभी पक्षी सोच में पड़ गए। उल्लू क्रोधित हो उठा और बोला, 'कौवे! तूने मेरे राज्याभिषेक में विघ्न डाला है। आज यदि यह समारोह रुक गया तो मैं तुझे और तेरे पूरे वंश को कभी क्षमा नहीं करूंगा।'

कौवा हंसकर उड़ गया। अभिषेक रुक गया और पक्षी बिना राजा चुने लौट गए। तभी से उल्लू और कौवों में बैर हो गया। उल्लू रात में कौवों को मारते हैं और कौवे दिन में उल्लुओं के घोंसलों को नष्ट कर देते हैं।

मार्ग खोजें

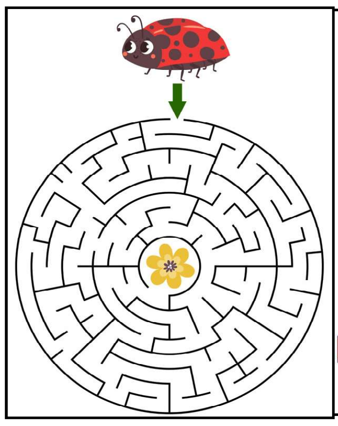

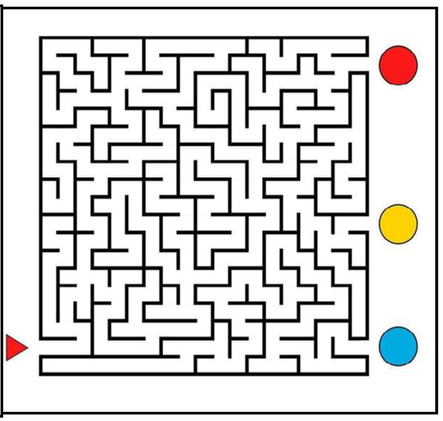

'बाहरी वोटरों' की बंगाल में एंट्री की कोशिश

ममता का आरोप सियासी घमासान

जन जन विचार
...कोलकाता

पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 'अवैध मतदाताओं' को राज्य की वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की जा रही है।

पश्चिम मिदनापुर के चंद्रकोना और गड़बेता में सभाओं को संबोधित करते हुए ममता ने दावा किया कि एक ही दिन में करीब 30 हजार फॉर्म जमा किए गए, जिससे मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर इसे 'अवैध और अलोकतांत्रिक' बताया।

मुख्यमंत्री ने लोगों से भाजपा से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि उनकी सरकार बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देगी। साथ ही केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया।

इन आरोपों के बीच बंगाल की राजनीति और गर्म हो गई है, जिससे आगामी चुनावों में मुकाबला और तीखा होने के संकेत मिल रहे हैं।

मतदाता सूची विवाद पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट

जन जन विचार
...नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर संतोष जताया है। अदालत को जानकारी दी गई कि कुल 60 लाख आपत्तियों में से लगभग 47.4 लाख का निपटारा 31 मार्च तक कर लिया गया है।

कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट के आधार पर शीर्ष अदालत ने कहा कि 7 अप्रैल तक सभी आपत्तियां निपट जाने की उम्मीद है और उसी दिन अगली सुनवाई होगी।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने से जुड़ी शिकायतें अपीलीय ट्रिब्यूनलों के सामने उठाई जा सकती हैं। इसके लिए 19 ट्रिब्यूनलों का गठन किया गया है, जिन्हें चुनाव आयोग के रिकॉर्ड तक पूरी पहुंच दी जाएगी।

अदालत ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ट्रिब्यूनलों के कामकाज में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। यह फैसला चुनावी माहौल में अहम माना जा रहा है।

केरल में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत

जन जन विचार
...तिरुवनंतपुरम/कन्नूर

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने राज्य में लगातार जनसभाएं की हैं।

कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि इस चुनाव का सीधा संबंध गांधी परिवार की साख से जुड़ा है, खासकर वायनाड से उनके जुड़ाव के कारण। यहां से पहले राहुल गांधी और वर्तमान में प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद हैं। पार्टी के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी राज्य में सक्रिय हैं। वहीं प्रियंका गांधी असम में चुनावी सभाओं के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बना रही हैं।

एंटी-इंकंबेंसी पर दांव

कांग्रेस को उम्मीद है कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेतृत्व वाली पिनाराई विजयन सरकार के खिलाफ दस वर्षों की सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इंकंबेंसी) का लाभ मिलेगा। राहुल गांधी ने कन्नूर में जनसभा को संबोधित करते हुए एलडीएफ पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वामपंथी दलों और भाजपा के बीच 'असामान्य गठजोड़' बन रहा है। उनके अनुसार, यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि विचारधाराओं की सीधी लड़ाई है।

मुस्लिम-इसाई वोटर्स की अहम भूमिका

केरल की राजनीति में सामाजिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण हैं। राज्य में जहां हिंदू मतदाता बहुसंख्यक हैं, वहीं मुस्लिम (लगभग 25 फीसदी) और इसाई (करीब 15 फीसदी) समुदाय मिलकर निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

कांग्रेस का गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ रहा है, जिससे उसे मुस्लिम वोट बैंक में मजबूती मिलती है। वहीं एलडीएफ और भाजपा की रणनीति इसाई मतदाताओं में पैठ बनाने पर केंद्रित है।

दिलचस्प चुनावी मुकाबला

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के प्रमुख प्रचारक के रूप में राहुल गांधी लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं-स्थानीय नेताओं से संवाद, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें और बड़े जनसमूह को संबोधित कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

स्पष्ट है कि केरल विधानसभा चुनाव 2026 सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी अहम परीक्षा बन चुका है-जहां कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की पूरी कोशिश में है।

एक परिवार असम को लूट रहा प्रियंका का हिमंत पर निशाना

जन जन विचार
...नयनमणि फुकन, नाजिरा

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि संसाधन संपन्न राज्य में केवल एक परिवार सब कुछ लूट रहा है, जबकि जनता के पास 'कुछ भी नहीं है'। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता को धमकाकर काम कर रही है।

कांग्रेस उम्मीदवार देवब्रत सैकिया के समर्थन में नाजिरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया और उन पर अमेरिका का 'गुलाम' होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि असम में एक परिवार सब कुछ लूट रहा है। और जब वे लूटपाट नहीं कर रहे होते हैं, तो खदानें, जमीनें और हर दूसरी संपत्ति बड़े उद्योगपतियों को सौंप दी जाती है।

असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हर मोर्चे पर व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, उन्होंने सारदा, स्मार्ट सिटी और एनसी हिल्स जैसे कई पुराने घोटालों का मुद्दा उठाया।

प्रियंका ने दावा किया कि भाजपा ने कहा कि उन्होंने दो इंजन वाली सरकार दी है। असल में, यह दो गुलामी वाली सरकार है।

प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की गुलामी में लगे हैं और हिमंत विश्व शर्मा मोदी की गुलामी में लगे हैं। उन्होंने चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के वादे को पूरा न करने के लिए भाजपा सरकार पर हमला किया।

उन्होंने असम के लोकप्रिय कलाकार जुबिन गर्ग की कथित रहस्यमय मौत की जांच पर भी सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने वादा किया कि अगर आगामी चुनावों में कांग्रेस समर्थित गठबंधन की सरकार बनती है, तो शपथ ग्रहण के 100 दिनों के भीतर इस मामले की जांच पूरी कर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। चौकीमुख में आयोजित सभा में उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भी लोगों से कांग्रेस समर्थित दलों की सरकार बनाने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करने वालों में भूपेश बघेल, देवब्रत सैकिया, अखिल गोगोई, अजय गोगोई, ज्ञान दीप मोहन, उत्पल गोगोई, पवन सिंह घटवार और डॉ. हेमप्रभा सैकिया सहित कई नेता शामिल रहे।

नक्सल डेडलाइन खत्म, 'नई रणनीति' पर फोकस

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

देश में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे अभियान के बाद 31 मार्च की तय डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। अमित शाह ने संसद में नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान करते हुए साफ संकेत दिए हैं कि अब सरकार की रणनीति सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि विकास और पुनर्वास पर केंद्रित होगी।

सरेंडर और पुनर्वास पर जोर : सरकार अब नक्सलियों के आत्मसमर्पण (सरेंडर) को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत 'नई सुबह' जैसी योजनाओं के जरिए हथियार छोड़ने वालों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जा रही है। लक्ष्य है-पूर्व नक्सलियों को रोजगार, शिक्षा और सामाजिक जीवन से जोड़ना।

विकास बनेगा सबसे बड़ा हथियार : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं का तेजी से विकास, पुलिस कैंप के आसपास स्वास्थ्य सेवाओं और स्कूलों का विस्तार, आदिवासी युवाओं को शिक्षा और कौशल से जोड़ना आदि। सरकार का मानना है कि विकास ही वह रास्ता है, जिससे नक्सलवाद की जड़ों को स्थायी रूप से खत्म किया जा सकता है।

जागरूकता और रोजगार पर फोकस : नई रणनीति में युवाओं को भटकने से रोकना सबसे अहम हिस्सा है। इसके लिए शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार योजनाओं को बढ़ाया जा रहा है, ताकि वे हिंसा के रास्ते से दूर रहें और मुख्यधारा में शामिल हों।

क्या खत्म होगी 'बंदूक की नीति' : हालांकि सुरक्षा बलों की तैनाती जारी रहेगी, लेकिन सरकार का फोकस अब 'बंदूक बनाम बंदूक' से हटकर 'विकास और विश्वास' की नीति पर है। यानी मुकाबले की जगह समावेशन को प्राथमिकता दी जा रही है।

असली चुनौती अब यह है कि नक्सलवाद दोबारा सिर न उठाए। इसके लिए सरकार को विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने, स्थानीय समुदायों का भरोसा जीतने और युवाओं को अवसर देने पर लगातार काम करना होगा। साफ है कि 31 मार्च के बाद की लड़ाई बंदूक से नहीं, बल्कि विकास, शिक्षा और विश्वास से लड़ी जाएगी।

'अश्वत्थामा' से सतर्क रहना जरूरी

जन जन विचार
...✍ डॉ. हिमांशु द्विवेदी

यह समय उल्लास का तो है... लेकिन उत्सव का नहीं। यह समय उम्मीद बांधने का तो है, साथ ही आशंका का भी है। यह समय अपेक्षाओं का भी ही है लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी का भी है। वह इसलिए क्योंकि भले ही पांडव अठारह दिन के भीषण संघर्ष के बाद महाभारत का युद्ध जीत गए लेकिन जीत के बाद निश्चिंतता की नींद ने उनके पक्ष के तमाम योद्धाओं को अश्वत्थामा के हाथों हमेशा के लिए सुला दिया था। वह तो द्वापर युग था तो एक ही अश्वत्थामा का अस्तित्व था। इस कलियुग में तो अब कौन अश्वत्थामा बन जाए, कहा नहीं जा सकता। महाभारत तो महज अठारह दिन का युद्ध था, नक्सलवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष की अवधि तो छह दशक की है।

बीस हजार से अधिक निर्दोष नागरिकों और हजारों सुरक्षाकर्मियों को मौत के घाट उतार देने वाले सशस्त्र नक्सलवाद को लेकर मोदी सरकार में गृहमंत्री अमित शाह ने जब 24 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ में दहाड़ते हुए कहा था कि, देश से हम 31 मार्च 2026 को इसे खत्म कर देंगे... तो लोग हैरत में पड़ गए थे। अमित शाह की राजनीतिक क्षमता और प्रशासनिक दक्षता के लोग कायल हैं लेकिन यह ऐलान तो बतौर ज्योतिषी महसूस हुआ था। वक्त गुजरने के साथ समझ में आने लगा कि, शाह ने यह दावा अंतरिक्ष में नक्षत्रों की स्थिति को देखकर नहीं बल्कि जमीं पर सुव्यवस्थित रणनीति बनाकर किया था।

यह उपलब्धि महज डेढ़ साल की मेहनत के आधार पर नहीं आई है। इसके पीछे वर्षों की मेहनत है। इस परिणाम की अभिलाषा पहले भी रही लेकिन उसके साथ दृढ़ इच्छाशक्ति, राज्य-केंद्र समन्वय, विभिन्न सुरक्षाबलों के मध्य समन्वय, आधुनिक तकनीक का अधिकाधिक उपयोग का अभाव वांछित परिणाम नहीं दे सका। सुरक्षाबल जब-जब हाथों में हथियार थाम घने जंगलों में छिपे दुर्दांत नक्सलियों के खिलाफ आपरेशन शुरू करते तो उनकी ढाल बन तमाम मानव अधिकारों के स्वघोषित पैरोकार सड़कों पर आ जाते थे।

जो विचारधारा संसदीय लोकतंत्र के खात्मे की अभिलाषा के साथ उपजी थी, उसकी पैरोकारी करने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि तो चिल्ला-चिल्ला कर अपने गले से खून तक निकाल लेते थे। वनांचल में नक्सली अपनी दहशत और हुकूमत बनाए रखने गोली- गोली चलाते रहते और शहरों में बैठे उनके हमदर्द बोली-बोली का राग अलाप कोई ठोस कार्रवाई करने में रोड़ा अटकाते रहते। लेकिन, इन परिस्थितियों में बदलाव तब आया जब 2024 में नक्सल उन्मूलन के वादे के साथ नरेंद्र मोदी सत्तारूढ़ हुए।

लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि, कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में यूपीए सरकार और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार के रहते सरगुजा अंचल से नक्सलियों को समाप्त करने में सफलता मिली थी। लेकिन, तिरुपति से पशुपति तक रेड कारिडोर की स्थापना की कोशिश कर रहे लोगों के खिलाफ यह सफलता पर्याप्त नहीं थी। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ रणनीति में बदलाव आया और अमित शाह के द्वारा गृह मंत्रालय की कमान संभालने के साथ ही यह संघर्ष निर्णायक दौर में पहुंच गया। सामाजिक और सामरिक दृष्टि से योजना बनाकर काम शुरू हुआ।

छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य की कमान वरिष्ठ आदिवासी नेता विष्णु देव साय के हवाले किया जाना भी इस कार्य-योजना का हिस्सा था। इस एक फैसले ने आदिवासियों में अपनी सरकार होने का विश्वास और नक्सलियों के प्रति अविश्वास पैदा किया। वह अपनी सरकार बंदूक की नली से लाने की बात कहते थे, यहां अपनी सरकार बैलेट से ही अस्तित्व में आते देखा गया। बंदूक की जगह संविधान पर आस्था पैदा करने के लिए जहां नक्सलियों को सुखद भविष्य का संदेश देती आकर्षक पुनर्वास नीति लाई गई, वहीं दशकों से विकास की बाट जोह रहे आदिवासी इलाकों के लिए 'नियद नेल्लानार' जैसा कार्यक्रम भी शुरू किया।

सुरक्षाबलों ने सटीक रणनीति और परस्पर समन्वय के साथ आक्रामक आपरेशन किए। उनके पराक्रम ने नक्सलियों के हाड़ कंपा दिए। छत्तीसगढ़ में इन कोशिशों के बीच गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का उल्लेख ना किया जाना ज्यादती होगी। घोर नक्सली इलाकों में अपनी जान हथेली पर रखकर वह जवानों का हौसला बढ़ाते रहे, वहीं नक्सलियों से संवाद के माध्यम से उन्हें समर्पण के लिए प्रेरित भी करते रहे। इन कोशिशों में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के उदार सहयोग और समर्थन ने संकल्प को सिद्धि में बदल दिया।

लेकिन, इस साझा प्रयास के परिणाम को सहेजना हमारी साझा जिम्मेदारी है। जिन अभावों से यह संघर्ष अस्तित्व में आया था, उन्हें खत्म करना ही होगा। स्कूल, हास्पिटल, सड़क, थानों के साथ इन इलाकों में युवाओं के लिए स्थाई रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। भूखे पेट और खाली हाथ कभी भी हथियार थाम सकते हैं, इस हकीकत को सरकार और समाज दोनों को ही बखूबी समझ लेना चाहिए।

क्या सचमुच खत्म हो गया नक्सलवाद!

नई दिल्ली/बस्तर। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के साथ देश में नक्सलवाद के 'खात्मे' का ऐलान किया गया। अमित शाह के इस दावे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है-क्या सचमुच नक्सलवाद खत्म हो गया है, या यह सिर्फ अपने अंतिम चरण में है?

आंकड़े क्या कहते हैं?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तस्वीर काफी बदली है-

2010 के मुकाबले नक्सली हिंसा में 70 प्रतिशत से अधिक गिरावट

126 जिलों से सिमटकर 30-35 जिलों तक सीमित प्रभाव

झारखंड और बिहार में लगभग समाप्त गतिविधियां

इन आंकड़ों से साफ है कि नक्सलवाद की पकड़ कमजोर जरूर हुई है।

ऑपरेशन और दबाव की रणनीति : पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों ने बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए, दुर्गम जंगलों में घुसकर कार्रवाई, 'अबूझमाड़' जैसे इलाकों में स्थायी कैंप, बड़े नक्सली नेताओं का सफाया।

इन कदमों ने नक्सलियों की सैन्य ताकत और नेटवर्क को गहरा नुकसान पहुंचाया है।

विकास बना बड़ा हथियार : सरकार ने रणनीति बदली-सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क का विस्तार। स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। युवाओं को रोजगार और शिक्षा से जोड़ने की कोशिश। इससे स्थानीय लोगों का झुकाव धीरे-धीरे मुख्यधारा की ओर बढ़ा है।

क्या पूरी तरह हुआ खत्म?

यहीं सबसे बड़ा सवाल है। जमीनी हकीकत कुछ और भी कहती है-

सीमावर्ती शरण : नक्सली एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बच निकलते हैं।

टॉप लीडरशिप : कई बड़े नेता अभी भी सक्रिय और भूमिगत हैं।

विचारधारा : नक्सलवाद सिर्फ हथियार नहीं, एक सोच भी है-जिसे खत्म करना लंबी प्रक्रिया है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि बंदूकधारी दस्तों को कमजोर करना आसान है, लेकिन विचारधारा को खत्म करना कठिन।

अंत नहीं, अंतिम चरण : साफ तौर पर कहा जा सकता है-

नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, लेकिन अपने सबसे कमजोर दौर में जरूर है। सरकार अपने लक्ष्य के बेहद करीब है, पर 'पूर्ण खात्मा' अभी प्रक्रिया में है।

31 मार्च 2026 एक प्रतीक बन सकता है-उस लड़ाई का, जो दशकों तक चली और अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

थमेगा मध्य पूर्व का संकट!

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

मध्य पूर्व में जारी तनाव को एक महीने से अधिक हो चुके हैं और अब हालात एक नए मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच संभावित संघर्ष विराम को लेकर बातचीत की खबरों ने वैश्विक स्तर पर उम्मीद और अनिश्चितता दोनों को जन्म दिया है।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ सीजफायर को लेकर चर्चा कर रहा है। इस बातचीत की सबसे बड़ी शर्त है-रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना। यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है, जिसके बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है।

हालांकि, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। यह भी तय नहीं है कि बातचीत सीधे हो रही है या किसी मध्यस्थ के जरिए। दूसरी ओर, ईरान ने आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन उसके राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने संकेत दिया है कि सुरक्षा गारंटी मिलने पर ही संघर्ष विराम संभव है।

अमेरिका की चिंता - ईरान का यूरेनियम भंडार

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, ईरान के पास करीब 440.9 किलोग्राम 60 फीसदी तक समृद्ध यूरेनियम है, जो हथियार-ग्रेड (90 प्रतिशत) से एक कदम दूर माना जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह भंडार सैद्धांतिक रूप से 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि, सैन्य कार्रवाई में रेडिएशन और रासायनिक खतरे के साथ भारी जोखिम जुड़ा है, इसलिए विशेषज्ञ कूटनीतिक समाधान को ही सुरक्षित रास्ता मानते हैं।

इसी बीच ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया कि ईरान बातचीत को तैयार है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक होर्मुज जलडमरूमध्य 'सुरक्षित और खुला' नहीं होता, तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। उनके कड़े तेवर और ईरान के सतर्क रुख के बीच स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन और ऊर्जा राजनीति से जुड़ा है। ऐसे में किसी भी संभावित समझौते का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिलहाल, निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति बंदूक की आवाज को दबा पाएगी या नहीं।

हर सिलेंडर पर 380 रुपए का घाटा, फिर भी नहीं बढ़ाई कीमत

14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 913 रुपए है

हर सिलेंडर पर सरकार को 380 रुपए का नुकसान

मई तक कुल घाटा करीब 40,484 करोड़ रुपए

पिछले साल सरकार का कुल घाटा 60,000 करोड़ रुपए का था

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

कच्चे तेल की कीमत में तेजी से दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में काफी तेजी आई है। देश में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में इसकी कीमत में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 7 मार्च को इसकी कीमत में 60 रुपए की इजाफा किया गया था। सरकार का कहना है कि तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर 380 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमत नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में कम है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत पर सरकार का नियंत्रण नहीं है और इसका निर्धारण बाजार के मुताबिक होता है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री और होटलों में होता है और हर महीने की पहली तारीख को इसकी कीमत में संशोधन होता है। देश में कुल एलपीजी खपत में कमर्शियल एलपीजी की हिस्सेदारी महज 10 फीसदी है।

बयान में कहा गया है कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में हुई ताजा बढ़ोतरी की वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत में काफी तेजी आई है। सऊदी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत में मार्च की तुलना में अप्रैल 44 फीसदी की तेजी आई है। मार्च के लिए यह 542 डॉलर टन थी जो अप्रैल के लिए 780 डॉलर पहुंच गई। ईरान युद्ध के कारण होर्मुज की खाड़ी से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे ग्लोबल एलपीजी सप्लाई की 20 से 30 फीसदी सप्लाई फंसी हुई है।

नेपाल : नो करप्शन, नो फियर

जन जन विचार
...✍ काठमांडू

काठमांडू से उठी एक सख्त और साहसिक पहल ने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्हें अब तक कोई सरकार छूने से भी कतराती रही। उनके 100 दिवसीय एक्शन प्लान में सबसे बड़ा और चर्चित कदम है-शिक्षण संस्थानों से छात्र राजनीति का पूर्णत: सफाया।

सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल और विश्वविद्यालय अब केवल शिक्षा के केंद्र होंगे, न कि राजनीतिक दलों के अड्डे। सभी राजनीतिक संगठनों को 60 दिनों के भीतर कैंपस खाली करने का आदेश दिया गया है। यह कदम उस लंबे दौर पर प्रहार माना जा रहा है, जब छात्र राजनीति के नाम पर शिक्षा का माहौल प्रभावित होता रहा।

बालेन शाह का यह निर्णय केवल प्रतिबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। सरकार 'स्टूडेंट काउंसिल' के रूप में एक गैर-राजनीतिक मंच विकसित करेगी, जहां छात्र अपनी समस्याएं रख सकेंगे और समाधान पा सकेंगे। इसका उद्देश्य छात्रों को विचारधाराओं का अनुयायी नहीं, बल्कि स्वतंत्र चिंतक बनाना है।

शिक्षा सुधार के तहत एक और बड़ा फैसला लिया गया है-कक्षा पांच तक पारंपरिक परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि बचपन को परीक्षा के दबाव से मुक्त कर रचनात्मकता और मौलिक सोच को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही विदेशी प्रभाव को कम करने के लिए उन शैक्षणिक संस्थानों के नाम बदलने का निर्देश दिया गया है, जिनके नाम विदेशी हैं। अब उन्हें स्थानीय पहचान के अनुरूप नेपाली नाम अपनाने होंगे।

बालेन सरकार का एजेंडा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सख्त अभियान छेड़ा गया है। एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो 2006 के बाद से बड़े पदों पर रहे नेताओं और अफसरों की संपत्ति की जांच करेगी।

जन जन की बात जन जन तक साप्ताहिक
जन जन विचार
RNI Regd No. ASMUL/25/A2367

Head Office : Golapi Market, 1st Floor, Beltola, Guwahati 781029
Branch Office : JanJan Vichar, GMCH Road, Harbala Market, Bhangagarh, Guwahati - 781005
Contact : 69001 26012
Email: official.janjanvichar@gmail.com
Website: WWW.janjanvichar.in

ग्राहक सदस्यता फॉर्म

ग्राहक विवरण

पूरा नाम : ....

पूरा पता : ....

....

मोबाइल : .... ह्वाट्सएप ....

ई-मेल (यदि हो) : ....

सदस्यता विवरण

अवधि : 1 वर्ष शुल्क : रु. 500/- मात्र

सदस्यता के साथ विज्ञापन लाभ

- सालभर (52 अंक) का अखबार नि:शुल्क मिलेगा
- एक नि:शुल्क विज्ञापन (10 सेमी. x 3 कॉलम)
- विज्ञापन प्रकाशन की तिथि ग्राहक की सुविधा अनुसार

भुगतान विवरण

☐ यूपीआई ☐ बैंक ट्रांसफर

Bank Details
JAN JAN VICHAR
Bank : HDFC, Branch : Guwahati
A/C No. 50200116979015
IFSC : HDFC0000264

इस क्यूआर कोड को स्कैन कर जन जन विचार के बैंक खाते में सीधे भुगतान कर सकते हैं।

(कृपया उपरोक्त में किसी एक माध्यम से ही भुगतान करें।)

भुगतान तिथि : .... रसीद संख्या:..........

घोषणा

मैं स्वेच्छा से जन जन विचार साप्ताहिक अखबार की एक वर्ष की सदस्यता ग्रहण करता/करती हूँ एवं सभी शर्तों से सहमत हूँ।

ग्राहक के हस्ताक्षर : तिथि :

कार्यालय उपयोग हेतु

सदस्यता क्रमांक: .... भुगतान प्राप्त रसीद संख्या:.......... प्राप्तकर्ता का नाम : ....

तिथि : .... हस्ताक्षर : ....

एफएलएन : शिक्षा की पहली मजबूत नींव

जन जन विचार
...✍ रामेश्वर शर्मा

भारत में शिक्षा की चर्चा अक्सर उच्च शिक्षा, तकनीक और रोजगार तक सीमित रह जाती है, लेकिन असल सवाल इससे कहीं पहले शुरू होता है-क्या हमारे बच्चे पढ़ना, लिखना और गिनना ठीक से सीख पा रहे हैं? यही बुनियादी कौशल, जिसे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (Foundational Literacy and Numeracy - FLN) कहा जाता है, आज देश के सामने सबसे बड़ी शैक्षिक चुनौती बनकर उभरा है।

बचपन : सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था

जन्म से लेकर 8 वर्ष तक का समय बच्चे के मस्तिष्क और व्यक्तित्व विकास का सबसे अहम दौर होता है। इसी समय बच्चे भाषा, गणित और सोचने-समझने की क्षमता विकसित करते हैं। घर का माहौल, माता-पिता की भूमिका और किताबें, कागज, रंग जैसे साधन बच्चे के सीखने की नींव रखते हैं।

बच्चे केवल पढ़कर नहीं, बल्कि करके सीखते हैं। खेल, प्रयोग, सवाल-जवाब और अनुभव उनके सीखने को मजबूत बनाते हैं। शिक्षक और अभिभावक अगर सही दिशा और सहयोग दें, तो बच्चा अपनी क्षमता को पूरी तरह विकसित कर सकता है।

क्या है साक्षरता और संख्यात्मकता: यूनेस्को के अनुसार साक्षरता केवल पढ़ना-लिखना नहीं, बल्कि समझना, विचार करना, संवाद करना और समस्याओं का समाधान करना भी है।

वहीं संख्यात्मकता का मतलब है-गणितीय समझ का उपयोग करके रोजमर्रा की समस्याओं को हल करना, जैसे गिनती, जोड़-घटाव, पैटर्न पहचानना और आंकड़ों को समझना।

क्यों जरूरी है एफएलएन: मजबूत साक्षरता और गणितीय कौशल न केवल पढ़ाई में मदद करते हैं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, आत्मनिर्भरता और देश की प्रगति से भी जुड़े होते हैं।

अगर बच्चे शुरुआती कक्षाओं में ये कौशल नहीं सीख पाते, तो आगे की पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और कई बार स्कूल छोड़ने तक की स्थिति बन जाती है।

देश में सीखने का संकट : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश में एक गंभीर लर्निंग क्राइसिस है। 5 करोड़ से अधिक बच्चे बुनियादी पढ़ने-लिखने और गणित में पीछे हैं। एक बार पिछड़ने के बाद बच्चे अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते। यह समस्या स्कूल छोड़ने का बड़ा कारण बन रही है।

यह स्थिति केवल शिक्षा की नहीं, बल्कि देश के भविष्य की चुनौती है।

सरकार की पहल - निपुण भारत मिशन : इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने निपुण भारत मिशन शुरू किया है।

इस मिशन का लक्ष्य है-2026-27 तक हर बच्चा कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करे। इसके तहत, प्री-स्कूल से कक्षा 3 तक स्पष्ट अधिगम लक्ष्य तय किए गए है। पढ़ाई को रटने से हटाकर समझ आधारित बनाया जा रहा है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम जैसे निष्ठा (NISTHA) चलाए जा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा (DIKSHA) का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

समाज की भागीदारी भी जरूरी : यह मिशन केवल सरकार या स्कूलों तक सीमित नहीं है। इसमें माता-पिता, परिवार और समाज की भागीदारी बेहद जरूरी है। अभिभावकों को घर में पढ़ने का माहौल बनाने, बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करने, सीखने को बोझ नहीं बनने देने और इसे आनंददायक बनाने में सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है।

भारत को ज्ञान आधारित समाज बनाने के लिए जरूरी है कि हर बच्चा मजबूत नींव के साथ आगे बढ़े। एफएलएन केवल शिक्षा का हिस्सा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है।

अगर आज हम बच्चों को पढ़ना, लिखना और गिनना सही ढंग से सिखा दें, तो आने वाला भारत न केवल शिक्षित होगा, बल्कि आत्मनिर्भर, सक्षम और जागरूक भी बनेगा।

निपुण असम मिशन का दिख रहा असर

निपुण असम मिशन असम सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो निपुण भारत मिशन के आधार पर शुरू की गई है। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता कौशल विकसित कर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए मजबूत आधार देना है।

इस मिशन के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास और नवाचारी शिक्षण पद्धतियों को लागू किया गया है। 45 हजार से अधिक स्कूलों में 100-दिवसीय पठन अभियान चलाकर बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा मिला है। 2024-25 में हजारों शिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया।

इस पहल का सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट दिख रहा है। बच्चे अब केवल पढ़ नहीं रहे, बल्कि समझकर सीख रहे हैं। कक्षा में शिक्षण अधिक बाल-केंद्रित और व्यावहारिक हुआ है। Teaching at the Right Level (TaRL) के माध्यम से बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, जिससे सीखने की खाई कम हो रही है।

समग्र रूप से, निपुण असम मिशन शिक्षा को रटने से समझने की दिशा में ले जा रहा है और बच्चों में आत्मविश्वास व सीखने की रुचि बढ़ा रहा है।

अग्निवीर भर्ती 2026 : आवेदन की तिथि बढ़ी

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 10 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।यह फैसला उन अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे।

पदों के लिए पात्रता

जीडी(जनरल ड्यूटी) : 10वीं पास, न्यूनतम 45% अंक
टेक्निकल : 12वीं पास (50% कुल, हर विषय में 40%)
क्लर्क/स्टोरकीपर : 12वीं पास (60%), इंग्लिश/मैथ्स में 50%
ट्रेड्समैन : 8वीं या 10वीं पास (33% अंक)
मिलिट्री पुलिस : 10वीं पास (45%)
आयु सीमा : न्यूनतम आयु :17.5 वर्ष, अधिकतम आयु : 21 वर्ष

कैसे करें आवेदन : उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : Join Indian Army Official Website वेबसाइट पर जाएं, Apply / Login पर क्लिक करें, नया रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन कर पूरी जानकारी भरें। 250 रुपए का आवेदन शुल्क जमा करें, फॉर्म सबमिट कर प्रिंट निकाल लें।

सीयूईटी 2026 :15 लाख छात्रों के बीच कड़ा मुकाबला

सीयूईटी यूजी 2026 में इस वर्ष 15.68 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। कुल आवेदनों का लगभग 60 प्रतिशत उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से है, जिससे इन राज्यों में कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। वहीं असम से भी लगभग 30-40 हजार छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जो पूर्वोत्तर में उल्लेखनीय है। यह दिखाता है कि असम के छात्र भी अब राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हो रहे हैं। इस परीक्षा के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में प्रवेश मिलेगा।

दस अप्रैल को जारी हो सकता है असम बोर्ड 10वीं का परिणाम

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

असम राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10 अप्रैल को हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एचएसएलसी) 2026 के नतीजे घोषित कर सकता है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के जरिए नतीजे देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

बोड कक्षा 10वीं की परीक्षा के नतीजों की 10 अप्रैल को करेगा। यह जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने साझा की थी। जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपना सही रोल नंबर डालकर रिजल्ट देख सकेंगे।

बोर्ड ने कक्षा 10 की परीक्षाएं 10 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थीं। असम एचएसएलसी में पास होने के प्रतिशत के अनुसार, छात्रों को हर विषय में कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाने होंगे। परीक्षा पास करने के लिए उन्हें कुल मिलाकर भी कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाने होंगे। इससे पहले, बोर्ड ने कहा था कि इस साल नतीजे जल्दी घोषित किए जाएंगे, असम राज्य विधानसभा चुनावों और बिहू त्योहार से पहले।

जुलाई में जिम्बाब्वे का दौरा करेगी टीम इंडिया

जन जन विचार
...✍ मुंबई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम इंडिया के जिम्बाब्वे दौरे की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। सीरीज के सभी मुकाबले हरारे में खेले जाएंगे। पहला मैच 23 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा। 25 जुलाई और 26 जुलाई को बाकी दो मैच भी इसी मैदान पर होंगे। यानी टीम इंडिया लगातार दो टी20 खेलेगी।

फैंस के सवाल : क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका

टीम इंडिया आखिरी बार 2024 में जिम्बाब्वे दौरे पर गई थी, जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी। यह सीरीज युवा खिलाड़ियों के लिए मौका बन सकती है। टी20 वर्ल्ड कप 2028 और ओलंपिक 2028 की तैयारियों को देखते हुए टीम कॉम्बिनेशन पर काम होगा। साथ ही बेंच स्ट्रेंथ को परखने का अच्छा मौका मिलेगा।

ऐसे में आईपीएल और जूनियर क्रिकेट में तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को भी मौका मिल सकता है। सूर्यवंशी पिछले महीने 15 साल के हो गए और अब आईसीसी के नियमों के अनुसार सीनियर भारतीय टीम के लिए खेलने के पात्र हो गए हैं। उन्होंने आईपीएल में अच्छे-अच्छे गेंदबाजों की धुलाई की है। ऐसे में बीसीसीआई उन्हें शामिल कर सकती है।

टीम इंडिया का व्यस्त कार्यक्रम

आईपीएल के बाद अफगानिस्तान से सीरीज

आईपीएल 2026 के खत्म होने के बाद सबसे पहले टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। अफगानिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आएगी। एकमात्र टेस्ट छह जून से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। वहीं, पहला वनडे 14 जून को धर्मशाला में, दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में और तीसरा वनडे 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा।

आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी टीम

अफगानिस्तान से सीरीज के बाद भारतीय टीम जून-जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करेगी। आयरलैंड में टीम इंडिया दो मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इसका पहला मुकाबला 26 जून को और दूसरा मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा। दोनों मुकाबले बेलफास्ट में ही खेले जाएंगे। इसके बाद टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। वहां टीम पांच टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला टी20 एक जुलाई को चेस्टर ली स्ट्रीट में, दूसरा टी20 चार जुलाई को मैनेचेस्टर में और तीसरा टी20 सात जुलाई को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इसके बाद चौथा टी20 नौ जुलाई को ब्रिस्टल में और आखिरी टी20 11 जुलाई को साउथैम्पटन में खेला जाएगा।

फिर इंग्लैंड से वनडे सीरीज खेलेगी टीम

फिर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत होगी। पहला वनडे 14 जुलाई को बर्मिंघम में, दूसरा वनडे 16 जुलाई को कार्डिफ में और तीसरा वनडे 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसी बीच टी20 टीम जिम्बाब्वे पहुंच जाएगी और फिर इंग्लैंड से वनडे सीरीज खत्म होने के बाद टीम जिम्बाब्वे से टी20 सीरीज खेलेगी।

चेन्नई सुपरकिंग्स की कमजोरियां

आईपीएल 2026

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

चेन्नई सुपरकिंग्स ने आईपीएल 2026 का आगाज हार के साथ किया है। वर्षापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहले ही मैच में चेन्नई की कई कमजोरियां उजागर हो गई हैं, जो इस सीजन में टीम की राह मुश्किल कर सकती हैं।

मिडिल ऑर्डर में अनुभव की कमी

चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर में अनुभव की कमी साफतौर पर पहले ही मैच में दिखाई दिए। संजू सैमसन और ऋतुराज के सस्ते में आउट होने के बाद टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने वाला कोई बल्लेबाज नजर नहीं आया। आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट जैसे बल्लेबाजों से चेन्नई की पारी बुनने की उम्मीद नहीं कर सकती है।

वहीं, घरेलू क्रिकेट में सरफराज ने बेशक खूब रन बनाए हैं, लेकिन आईपीएल में उनका रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर अभी काफी युवा हैं। अनुभव के नाम पर चेन्नई के मध्यक्रम में सिर्फ शिवम दुबे एक बल्लेबाज नजर आते हैं। यह भी सच्चाई है कि दुबे हर मुकाबले में टीम की नैया को शायद अकेले पार ना लगा सकें।

फिनिशर की कमी

सिर्फ मिडिल ऑर्डर ही नहीं बल्कि चेन्नई सुपरकिंग्स को इस सीजन एक दमदार फिनिशर की कमी भी खल सकती है। डेवाल्ड ब्रेविस यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, लेकिन वह चोटिल हैं और उन्हें पूरी तरह से फिट होने में कितना समय लगेगा यह कहना मुश्किल है। एमएस धोनी भी दो हफ्ते के लिए उपलब्ध नहीं हैं। टीम प्रशांत वीर और उर्विल पटेल को यह रोल दे सकती है, लेकिन इन दोनों के पास अनुभव की कमी है।

कमजोर गेंदबाजी अटैक

चेन्नई का गेंदबाजी अटैक इस सीजन टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। मैट हेनरी का रिकॉर्ड टी-20 में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है और इसका उदाहरण पहले ही मैच में देखने को भी मिला। राजस्थान के खिलाफ हेनरी ने तीन ओवर के स्पेल में ही 40 रन खर्च कर दिए थे। खलील अहमद और अंशुल कंबोज से टीम दमदार प्रदर्शन की उम्मीद कर सकती है।

हालांकि, खलील विकेट निकालने की काबिलियत तो रखते हैं, लेकिन वह काफी महंगे साबित होते हैं। स्पिन विभाग में नामी गेंदबाज के तौर पर टीम के पास सिर्फ नूर अहमद और अकील हुसैन ही दिखाई दे रहे हैं। चेन्नई के साथ दिक्कत यह है कि इन दोनों विदेशी गेंदबाजों को टीम एक साथ प्लेइंग इलेवन में नहीं खिला सकती है। नूर राजस्थान के खिलाफ रनों पर लगाम लगाने में भी विफल रहे थे।

नेहा पौड़ेल ने बढ़ाया उदालगुड़ी का मान

राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुई चयनित

जन जन विचार
...✍ प्रांजल कुमार शर्मा
माजबाट

असम के खेल जगत से एक गर्वित करने वाली खबर सामने आई है। नेहा पौड़ेल ने नगांव में 23 से 27 मार्च तक हुई 46वीं अंतर-जिला बालक-बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर वर्ग (63-66 किलोग्राम) में स्वर्ण पदक जीतकर ओरांग और उदालगुड़ी जिले का नाम रोशन किया है।

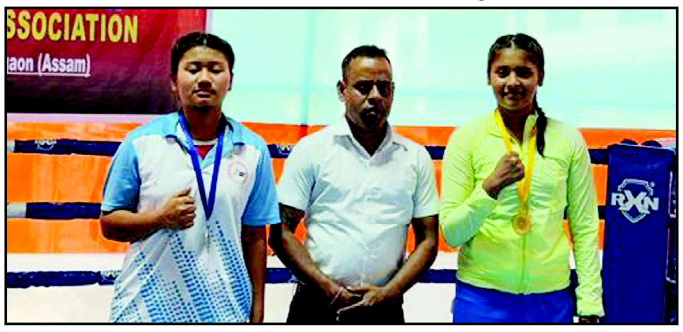

इस उपलब्धि के साथ ही नेहा का चयन आगामी अप्रैल में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। यह उनके उज्वल भविष्य और प्रतिभा का प्रमाण है।

नेहा यूरेका इंग्लिश स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा हैं। वह ओरांग के हाबीगांव निवासी होटल व्यवसायी गोविंद पौड़ेल और शांति देवी की पुत्री हैं। नेहा की इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की है। नेहा पौड़ेल की यह उपलब्धि साबित करती है कि प्रतिभा किसी स्थान की मोहताज नहीं होती।

बेथलीन ग्रेस की सफलता

जगदलपुर। बेथलीन ग्रेस माकरी ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में महिलाओं की रेस-वॉकिंग प्रतियोगिता में कांस्य (ब्रॉन्ज) पदक जीता। यह उनकी पहली बड़ी प्रतियोगिता थी। उन्होंने 1 घंटे 5 मिनट 18 सेकेंड में रेस पूरी की। बेथलीन पहले मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रनर थीं, लेकिन 2026 में उन्होंने रेस-वॉकिंग शुरू की। शुरुआत में उन्हें इस खेल को सीखने में काफी कठिनाई हुई।

दादा- द सौरव गांगुली स्टोरी

गांगुली बायोपिक की शूटिंग शुरू

राजकुमार राव ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की। फिल्म का नाम 'दादा- द सौरव गांगुली स्टोरी' है, जो पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली पर आधारित होगी। उन्होंने पोस्ट शेयर कर कैप्शन दिया- और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिल्म को लव फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है।

पोस्ट शेयर करने के बाद बॉलीवुड सेलेब्स ने भी एक्टर को उनके प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं दी हैं। फराह खान, नेहा धूपिया और सचेत टंडन ने पोस्ट पर 'ऑल द बेस्ट' कमेंट किया। वहीं ऋत्विक साहोरे, अपारशक्ति खुराना और ईशा अग्रवाल ने भी एक्टर की पोस्ट पर कमेंट कर बधाई दी।

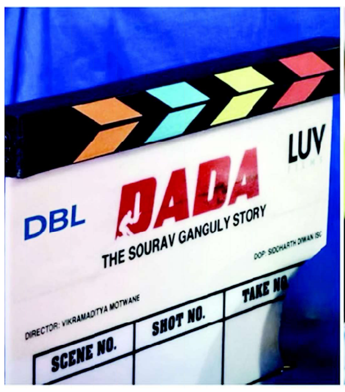

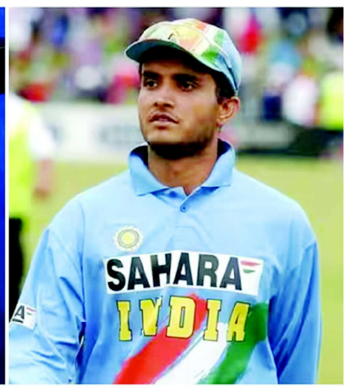

फिल्म के बारे में

फिल्म को विक्रमादित्य मोटवानी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली, जिन्हें 'दादा' के नाम से जाना जाता है, उनके जीवन और उनके क्रिकेटिंग करियर पर आधारित होगी।

इस मूवी पर काफी समय से काम चल रहा था, और इसके लिए राजकुमार राव ने वजन भी घटाया है। राजकुमार राव अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, और इस रोल के लिए उन्होंने खास तैयारी भी की है। हालांकि अभी तक फिल्म की अन्य कास्ट और इसकी रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है।

सौरव गांगुली को 'दादा' कहा जाता है और उन्हें भारतीय क्रिकेट को नई आक्रामक पहचान देने का श्रेय दिया जाता है। उनकी कहानी संघर्ष, नेतृत्व और वापसी की कहानी है-जो बड़े पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प होगा।

'धुरंधर 2' का दबदबा कायम

जन जन विचार ...मुंबई

सिनेमाघरों में इन दिनों धुरंधर 2 का जलवा बरकरार है। रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म रिलीज के दो हफ्ते बाद भी शानदार कमाई कर रही है और नए रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है।

फिल्म ने अपने 13वें दिन 27.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो बारहवें दिन के 25.30 करोड़ रुपये से अधिक है। इसी के साथ फिल्म की कुल घरेलू कमाई 856.92 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। फिल्म अब 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने के बेहद करीब मानी जा रही है।

वहीं, वैश्विक स्तर पर भी फिल्म का प्रदर्शन दमदार रहा है। 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1435.41 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिससे इसने अपने पहले भाग के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।

दूसरी ओर, हॉलीवुड फिल्म प्रोजेक्ट हेल मेरी 'धुरंधर 2' के सामने टिकने की कोशिश कर रही है। फिल्म ने अपने छठे दिन 2.95 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे इसका कुल कलेक्शन 19.78 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि, बड़ी हिंदी फिल्म के मुकाबले यह आंकड़ा कमजोर माना जा रहा है।

इसके अलावा, उस्ताद भगत सिंह भी बॉक्स ऑफिस पर खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। फिल्म ने 13वें दिन महज 35 लाख रुपए का कारोबार किया है। कुल मिलाकर 13 दिनों में फिल्म की कमाई 70.64 करोड़ रुपये तक ही सीमित रही है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नहीं दिखेंगी 'दयाबेन'

जन जन विचार ...मुंबई

लोकप्रिय टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 'दयाबेन' की वापसी को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब एक नया मोड़ आ गया है। शो में मिसेज सोढ़ी का किरदार निभा चुकीं जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने दावा किया है कि दिशा वकानी अब कभी शो में वापसी नहीं करेंगी।

जेनिफर मिस्त्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि दिशा वकानी के कमबैक को लेकर जो खबरें सामने आती हैं, वे केवल दर्शकों को जोड़कर रखने की 'मार्केटिंग स्ट्रैटिजी' है। उनका कहना है कि जब वह शो का हिस्सा थीं, तब भी दयाबेन के रोल के लिए दूसरी अभिनेत्री का ऑडिशन लिया गया था और मॉक शूट तक किया गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि साल 2021 में दिशा वकानी की वापसी लगभग तय हो गई थी। जेनिफर के मुताबिक, दिशा ने शूट से पहले कॉस्ट्यूम ट्रायल भी किया था, लेकिन अचानक योजना बदल गई और वह शो में नहीं लौटीं। इस मामले में जेनिफर ने दिशा के ससुराल पक्ष की शर्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दिशा के परिवार की ओर से कुछ सीमाएं तय थीं- जैसे देर रात शूटिंग न करना, लंबे घंटे काम न करना आदि। हालांकि, शो के निर्माता असित कुमार मोदी इन शर्तों से सहमत नहीं हुए।

गौरतलब है कि दिशा वकानी ने साल 2017 में मातृत्व के बाद शो छोड़ दिया था। तब से लेकर अब तक उनकी वापसी को लेकर कई बार दावे किए गए, लेकिन वह अब तक पर्दे पर नहीं लौटीं।

पहाड़, समंदर और खुली आजादी

तेजी से बढ़ रहा कैरावैन ट्रैवल का ट्रेंड

जन जन विचार ...मुंबई

बदलती लाइफस्टाइल और 'फ्रीडम ट्रैवल' की चाह के बीच भारत में कैरावैन टूरिज्म एक नए ट्रेंड के रूप में तेजी से उभर रहा है। होटल के बंद कमरों से बाहर निकलकर अब लोग पहाड़ों, समुद्र और जंगलों के बीच अपना चलता-फिरता आशियाना बसाना पसंद कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के इगतपुरी की वादियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक, कैरावैन ट्रैवल एक नई 'ट्रैवल संस्कृति' बनकर सामने आ रहा है-जहां सफर पूरी तरह आपके नियंत्रण में होता है।

क्या है कैरावैन ट्रैवल

कैरावैन एक ऐसा चलता-फिरता घर है, जिसमें आपको मिलती हैं- सोने के लिए बेड और आरामदायक स्पेस, छोटा किचन और फ्रिज, बाथरूम (बायो-टॉयलेट, शॉवर), एसी, टीवी जैसी सुविधाएं।

यानी घर जैसा आराम और एडवेंचर दोनों एक साथ।

महंगा लेकिन यादगार अनुभव

कैरावैन ट्रिप की कीमत 12,000-15,000 रुपए प्रतिदिन तक हो सकती है। यह हर किसी के बजट में नहीं है, लेकिन जो एक बार इसे आजमाता है, उसके लिए यह सिर्फ खर्च नहीं-एक याद बन जाता है।

बढ़ रहा ट्रेंड

भारत में खासकर शहरी युवाओं के बीच यात्रा को लेकर सोच तेजी से बदल रही है। अब लोग 'देखने' से ज्यादा 'महसूस करने' वाले सफर की ओर बढ़ रहे हैं। भीड़भाड़ वाले टूर पैकेज और रिजॉर्ट्स की जगह अब लोग खुली हवा, कम भीड़ और निजी स्पेस को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही वजह है कि कैरावैन टूरिज्म धीरे-धीरे एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बनता जा रहा है।

बढ़ते ट्रेंड के कारण हैं- होटल की पाबंदियों से आजादी, भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के करीब अनुभव, जहां मन करे, वहीं रुकने की सुविधा, सोशल मीडिया और व्लॉगिंग का बढ़ता असर। युवाओं और फैमिली ट्रैवलर्स के बीच यह तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, खासकर मेट्रो शहरों में।

पूर्वांचल प्रिंटर्स की ओर से राजनाथ पाल द्वारा जीएमसीएच रोड, हरबाला मार्केट, भांगागढ़, गुवाहाटी-781005 से प्रकाशित एवं मुद्रित। संपर्क : 69001 26012
ई-मेल:official.janjanvichar@gmail.com, वेबसाइट: www.janjanvichar.in ● कार्यकारी संपादक : सुभाष कुमार चौधरी ●संपादक : धनेश्वर चौधरी